

प्रेषक,

संख्या: 1/3 नू०क्य / 18(1) / 2006

राजस्व प्रबन्धाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग

दिव्ययः—दी०एस०होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स (इण्डिया) लि० को तहसील रामनगर के ग्राम दिकुली में होटल एंव रिसोर्ट की स्थापना हेतु कुल 1.654 हेठो भूमि क्य करने वी अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक: 2 अगस्त, 2006

जून, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दी०एस०होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स (इण्डिया) लि० को होटल एंव रिसोर्ट की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उ०प्र० जर्मीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की घारा-154(4)(3)(क)(II) के अन्तर्गत तहसील रामनगर के ग्राम दिकुली में कुल 1.654 हेठो भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं—

1— केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिकर दना रहेगा और ऐसा भूमिकर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अई होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिकरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लागू की गयी विधियों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की रिपोर्ट से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे मिल किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे मिल प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण चलता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा। और धारा-157 के परिणाम लागू होंगे।

(2)

4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तापित है उसके भूखामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिकर होने की विधति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुभाति प्राप्त की जायेगी।

5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तापित है उसके भूखामी असंकगणीय अधिकार घाले भूमिकर न हों।

6— स्थापित किये जाने वाले होटल/रिसोर्ट में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिरक्षत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

7— निवेशक द्वारा जिलाधिकारी को माछ्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन को उपलब्ध करादी जायेगी।

8— उपरोक्त शतों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा जिसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत त्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

ये पथ तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीम्

(एन०एस०नपलच्चाल)
प्रमुख सचिव।

निया एवं तितिका

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2— आयुक्त, कुमाऊँयू मण्डल, नैनीताल।
- 3— प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4— श्री अमृल जैन, डायरेक्टर, डी०एस०होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स (इण्डिया) लि० 1711
एन०पी०मुखर्जी मार्ग, दिल्ली।
- 5— नियोगक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल सचिवालय।
- 6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(तुनील सिंह)
अनुसंचित।